भारत सरकार

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग

उड़ीसा ओबीसी वैलफेयर विभाग के साथ बैठक का कार्यवृत्त

दिनांक 11.02.2020

NCBC/08/01/209-A/2020/KSP

बैठक में उपस्थित अधिकारीः-

1. डॉ भगवान लाल साहनी, माननीय अध्यक्ष, रा.पि.व.आ.
2. डॉ लोकेश कुमार प्रजापति, माननीय उपाध्यक्ष, रा.पि.व.आ.
3. श्री कौशलेन्द्र सिहं पटेल, माननीय सदस्य, रा.पि.व.आ.
4. डॉ सुधा यादव, माननीय सदस्य, रा.पि.व.आ.
5. श्री आचार्य थल्लोजु, माननीय सदस्य, रा.पि.व.आ.
6. श्री बी.के. पति, उप सचिव, रा.पि.व.आ.
7. श्री अभय, डीजीपी, उड़ीसा सरकार
8. श्रीमति रंजना चौपड़ा, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, बी.सी. बेलफेयर विभाग, उड़ीसा सरकार
9. श्री पी.के. सेनापति, डायरेक्टर, बी.सी. बेलफेयर विभाग, उड़ीसा सरकार
10. अन्य अधिकारीगण, उड़ीसा सरकार

डॉ भगवान लाल साहनी, माननीय अध्यक्ष, रा.पि.व.आः- उड़ीसा राज्य में ओबीसी का कुल आबादी कितनी है?

प्रिंसिपल सेक्रेटरीः- सर, ओबीसी जाति की अलग से जनगणना नही होती है इसलिए ओबीसी की आबादी का जानकारी नही है हमने भारत सरकार को ओबीसी की अलग से जनगणना के लिए लिखा है।

श्री कौशलेन्द्र सिहं पटेल, माननीय सदस्य, रा.पि.व.आः- ओबीसी को 11.25% आरक्षण नौकरी व एजुकेशन दोनों में दिया जा रहा है?

प्रिंसिपल सेक्रेटरीः- सर, ओबीसी को अभी हम सिर्फ नौकरी में 11.25% आरक्षण दे रहे है एजुकेशन में ओबीसी को आरक्षण नही दिया जा रहा है। हम दूसरे राज्यों का डाटा देख रहे है।

श्री कौशलेन्द्र सिहं पटेल, माननीय सदस्य, रा.पि.व.आः- यह तो बहुत ही आश्चर्यजनक है कि ओबीसी को एजुकेशन में आरक्षण नही दिया जा रहा है। जब आदमी पढ़ेगा ही नही तो वह नौकरी कहा से करेगा।

प्रिंसिपल सेक्रटरीः- सर, अभी हम इसको एक्जामिन कर रहे है।

श्री कौशलेन्द्र सिहं पटेल, माननीय सदस्य, रा.पि.व.आः- कब तक इसको एक्जामिन कर लोगे?

प्रिंसिपल सेक्रटरीः- सर, हम कोई निश्चित समय नही बता सकते है।

श्री कौशलेन्द्र सिहं पटेल, माननीय सदस्य, रा.पि.व.आः- अभी तक उड़ीसा राज्य में ओबीसी आयोग का भी गठन नही किया गया है?

प्रिंसिपल सेक्रेटरीः- सर, यह अभी विचाराधीन है।

श्री कौशलेन्द्र सिहं पटेल, माननीय सदस्य, रा.पि.व.आः- उड़ीसा राज्य को ओबीसी के काफी लोग आए हुए थे और उनकी मुख्य मांग थी कि यहां पर भी ओबीसी आयोग का गठन होना चाहिए।

प्रिंसिपल सेक्रेटरीः- सर, इस मामले में अभी हम दूसरे राज्यों से जानकारी ले रहे है। हम आपकी ये रिकमन्डेशन मुख्यमंत्री जी को देंगे।

डॉ भगवान लाल साहनी, माननीय अध्यक्ष, रा.पि.व.आः- कई राज्यों जैसे तमिलनाडू, कर्नाटक आदि में ओबीसी को 50% से भी अधिक रिजर्वेशन दिया जा रहा है।

श्री कौशलेन्द्र सिहं पटेल, माननीय सदस्य, रा.पि.व.आः- उड़ीसा राज्य में ओबीसी, एससी व एसटी में कितनी-कितनी जातियां है?

प्रिंसिपल सेक्रेटरीः- सर, ओबीसी में 200, एससी में 93 व एसटी में 62 जातियां है।

श्री कौशलेन्द्र सिहं पटेल, माननीय सदस्य, रा.पि.व.आः- 200 जातियों के लिए सिर्फ 11.25% रिजर्वेशन दिया जा रहा है और बाकी के लिए 39% रिजर्वेशन दिया जा रहा है।

प्रिंसिपल सेक्रेटरीः- सर, रिजर्वेशन जातियों की संख्या पर नही बल्कि उनकी जनसंख्या पर निर्भर करता है।

श्री कौशलेन्द्र सिहं पटेल, माननीय सदस्य, रा.पि.व.आः- ओबीसी वेलफेयर के लिए कितना बजट आवंटित किया गया है?

प्रिंसिपल सेक्रेटरीः- सर, लगभग 70 करोड़ रूपये, सभी योजनाओं स्किल डेवलेपमेंट आदि को मिलाकर।

श्री कौशलेन्द्र सिहं पटेल, माननीय सदस्य, रा.पि.व.आः- ओबीसी के लिए कौन-कौन सी योजनाएं चलायी जा रही है?

प्रिंसिपल सेक्रेटरीः- सर, ओबीसी हॉस्टल योजना के लिए 47 करोड़ रूपये का बजट आवंटित किया गया है।

श्री कौशलेन्द्र सिहं पटेल, माननीय सदस्य, रा.पि.व.आः- यह योजना कब से शुरू की गयी है और अभी तक कितने हॉस्टल बने है?

प्रिंसिपल सेक्रेटरीः- सर, 100 हॉस्टल बनने है और सभी जिलों में 76 बन चुके है। एक कटक में है, एक भुवनेश्वर में है लेकिन यह अभी शुरू नही हुए है। 16-17 प्री-मैट्रिक के लिए और बाकी पोस्ट-मैट्रिक के है।

डॉ भगवान लाल साहनी, माननीय अध्यक्ष, रा.पि.व.आः- उड़ीसा राज्य में एजुकेशन में ओबीसी को आरक्षण नही दिया जा रहा है। ओबीसी में बहुत सी जातियां ऐसी है जिनकी हालत एससी व एसटी से भी खराब है। एडमीशन में तो आरक्षण देना चाहिए।

श्री कौशलेन्द्र सिहं पटेल, माननीय सदस्य, रा.पि.व.आः- उड़ीसा राज्य में केन्द्र सरकार की कौन-कौन सी योजनाएं चलायी जा रही है?

प्रिंसिपल सेक्रेटरीः- स्किल डेवलेपमेंट ट्रेनिंग तथा स्कालरशिप स्कीम सिर्फ यहीं योजनाए चलायी जा रही है बाकी राज्य सरकार की योजनाएं है।

श्री कौशलेन्द्र सिहं पटेल, माननीय सदस्य, रा.पि.व.आः- प्री-मैट्रिक व पोस्ट-मैट्रिक में कितने-कितने छात्रों को स्कालरशिप दी गयी है?

प्रिंसिपल सेक्रटरीः- सर, प्री-मैट्रिक में 1,11,618 ओबीसी को छात्रों को स्कालरशिप दी गयी है इसमें 50% केन्द्र सरकार व 50% राज्य सरकार देती रही है। पोस्ट-मैट्रिक में 1,38,000 को दी गयी है।

श्री कौशलेन्द्र सिहं पटेल, माननीय सदस्य, रा.पि.व.आः- बैंक भी ओबीसी के छात्रों को लोन नही दे रहे है हमने कई बैंको को रिव्यू किया है।

प्रिंसिपल सेक्रेटरीः- सर, इसी सरकार ने ओबीसी को नौकरी में रिजर्वेशन दिया है इससे पहले किसी सरकार ने ओबीसी को रिजर्वेशन नही दिया है।

श्री कौशलेन्द्र सिहं पटेल, माननीय सदस्य, रा.पि.व.आः- क्रीमी-लेयर व नॉन क्रीमी-लेयर का प्रमाण पत्र कैसे दिया जाता है? अगर में बी ग्रेड का ऑफिसर हूँ और मेरी आय 8 लाख से अधिक है तो क्या मुझे नान-क्रीमी लेयर का प्रमाण पत्र मिल सकता है?

निदेशक, ओबीसी, उड़ीसा सरकारः- नही सर, आपको नही मिलेगा।

श्री कौशलेन्द्र सिहं पटेल, माननीय सदस्य, रा.पि.व.आः- यह तो पूरी तरह से पिछड़ी जातियों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है जब इतने बड़े अधिकारियों को ही नही पता है तो नीचे वालों का कहां से पता लगेगा।

प्रिंसिपल सेक्रेटरीः- सर, हमने अभी कुछ समय पहले ही जॉइन किया है इसलिए ज्यादा जानकारी नही है। हमने यह नोट कर लिया है हम इसका परीक्षण करेंगे और नीचे से फीडबैक लेंगे।

डॉ भगवान लाल साहनी, माननीय अध्यक्ष, रा.पि.व.आः- आप लोग क्रीमी-लेयर की धारणा को सही करिये।

श्री कौशलेन्द्र सिहं पटेल, माननीय सदस्य, रा.पि.व.आः- 11.25% रिजर्वेशन एजुकेशन में भी शुरू करवाइये अगर राज्य सरकार चाहे तो 27% आरक्षण भी ओबीसी को दिया जा सकता है। 50% वाला वैरियर EWS से टूट गया है।

डीजीपी, उड़ीसाः- सर कोर्ट से हो जायेगा तो हम दे देगें।

श्री कौशलेन्द्र सिहं पटेल, माननीय सदस्य, रा.पि.व.आः- एजुकेशन में तो 11.25% रिजर्वेशन शुरू कीजिए।

सुनवाई सम्पन्न।

(कौशलेन्द्र सिहं पटेल)
सदस्य, रा.पि.व.आ.